[श्री धर्मवीर]

हाजिर हो गये हैं। अब कोर्ट उनको जमानत पर छोड़ दे तो न्यायालय इसके लिये सक्षम हैं। चाहे वह जमानत ले ले या सजा दे दे।

I have tried my best to meet all the points raised by the hon. Members and I want to express my gratitude to all the Members who have placed these facts before the Government. I am thankful to the press as well as to the hon. Members who raised different points here and brought these facts before us. I assure the House that at no cost are we going to tolerate this system.

Regarding the brick kiln industry I once again tell that we cannot tolerate the exploitation of the labourers, the workers in any industry in the country.

15.38 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Sixty-First Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): Sir, with your permission I beg to move:

> "That this House do agree with the Sixty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 23rd April, 1984."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That this House do agree with the Sixty-first Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 23rd April, 1984."

The Motion was adopted.

15.40 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to withdraw excise duty on P.V.C. Films, manufactured by Calendering process

श्री मेनोराम बागड़ी (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में गत 20 वर्षों से पी०वी०सी० फिल्मों का केलेंडरिंग प्रक्रिया से निर्माण हो रहा है। सरकार ने 6 मध्यम दर्जे के ऐसे कारखानों को इसका लाइसेंस दिया है, जो हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। मई, 1971 में सभी किस्म की पी०वी०सी० फिल्मों का उत्पादन-शुल्क की परिधि में ला दिया गया था। इसके बाद मार्च, 1973 में छोटे कारखानों में केवल एक्सट्रूजन प्रक्रिया द्वारा निर्मित पी०वी०सी० फिल्मों की पूर्ण रूप से उत्पादन-शुल्क की अदायगी की छूट दे दी गई थी। स्पष्टतया ऐसा एक्सट्रूजन कारखानों को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। उक्त छूट के फलस्वरूप गत दस वर्षों के दौरान, एक्सट्रूजन कारखानों का उत्पादन लगभग 12000 मी०टन प्रति-वर्ष रहा है।

केलेंडर पी०पी०सी० फिल्मों पर उत्पादन-शुल्क की वर्तमान दर 31½ प्रतिशत है। कैलेंडर पी०वी०सी० फिल्मों तथा एक्सट्रूडिड पी०वी०सी० फिल्मों के बीच इतने भारी अंतर के कारण कैलेंडर कारखाने अपना उत्पादन नहीं बेच पाए।

कैलेंडर कारखानों की 16,3000 मी० टन प्रति-वर्ष की अधिष्ठापित क्षमता के बजाए गत वर्ष का उत्पादन मुश्किल से ही लगभग 6500 मी० टन प्रति-वर्ष रहा था, जबकि एक्सट्रूजन कारखानों का उत्पादन 12,000 मी० टन प्रति-वर्ष रहा था।

कैलेंडरिंग तथा एक्सट्रूजन प्रक्रिया से बनाई गई फिल्मों के उपभोक्ता तथा उसका प्रयोग दोनों ही एक समान हैं। इस लिए उपभोक्ता कैलेंडर पी०वी०सी० फिल्मों का अधिक दाम देने के लिए तैयार नहीं होते। अखिल भारतीय कैलेंडर पी०वी०सी० फिल्म निर्माताओं ने पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान समय-समय पर वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्री महोदय तथा डी०जी०टी०डी० को अनेकों अभ्यावेदन दिए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

निर्णय में विलंब के कारण पी०वी०सी० बनाने वाले कई कारखाने बन्द हो गए हैं, जिसके फल-

स्वरूप हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। यदि उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई, तो वह दिन दूर नहीं, जब यह उद्योग समाप्त हो जाएगा।

IMA

अतः अनुरोध है कि कैलेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा बनाई जा रही पी०वी०सी० फिल्मों पर लगाया गया 31½ प्रतिशत उत्पादन-शुल्क समाप्त कर दिया जाए और कैलेंडरिंग कारखानों द्वारा खरीदे गए मौलिक कच्चे माल पर वसूल किया गया शुल्क वापस किया जाए।

(ii) Need to effect basic changes in the field of research

श्री मूल चन्द डागा (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, वैज्ञानिक जगत में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना है। विज्ञान के चरण बहुत तेज और तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए भारत सरकार ने करीब 150 प्रयोगशालाएं खोल रखी हैं, जहां बड़े और छोटे वैज्ञानिकों द्वारा शोधकार्य होता है। केन्द्रीय सरकार हर साल 570 करोड़ रुपया इन शोध प्रयोगशालाओं पर खर्च करती है। यह बात निर्विवाद सही है कि इन शोधशालाओं से आज लगभग शून्य है, जबकि खर्च उसकी तुलना में बढ़ा-चढ़ा है। क्या आज तक कभी इस बात का मूल्यांकन किया गया है कि ये शोधशालाएं समाज की कौन-कौन सी जरूरतों को मद्देनजर रख कर काम कर रही हैं और इनकी उपलब्धियां पिछले पांच वर्षों में जो हुई हैं, क्या वे सन्तोषजनक हैं? आज वैज्ञानिक जगत में बढ़े हुए देश अमरीका, रूस, यूरोप में वैज्ञानिकों और उद्योगों के बीच में गहरा जिन्दा लेन देन दिखाई पड़ता है। समस्या और समाधान के बीच जो सुन्दर और सलोने पुल बंधे हुए हैं, भारत में उन का सर्वथा अभाव है। इन शोधशालाओं में वैज्ञानिकों की ज्यादा ताकत शोध करने में नहीं, फार्म भरने में और प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार करने में लगाई जाती है। आज कई वैज्ञानिक शोधशालाओं में शानदार उपलब्धि के बजाय शानदार प्रोग्रेस रिपोर्ट उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार के माहौल ने अच्छे वैज्ञानिकों को विदेश जाने के लिए मजबूर किया है और जो बाहर हैं, वे भारत लौटने को आतुर नहीं हैं। अतः सरकार को शोध के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन और परिवर्धन करना होगा ताकि जो धनराशि खर्च होती है, उससे समाज और देश को लाभ मिल सके और वैज्ञानिक जगत में भारत प्रगतिशील देशों की दौड़ में पीछे न रहे।

(iii) Need for setting up proposed Railway Coach Factory in Palghat, Kerala

***SHRI V.S. VIJAYARAGHAVAN** (Palghat): Sir, Kerala is an industrially backward State. For the past many years a demand has been raised for setting up a railway coach factory in that State. The Government of Kerala had promised to provide all infrastructural facilities at concessional rates. As a matter of fact, there is no major railway installation in Kerala.

Now, there is a report that an expert team has been sent to Kerala to make preliminary study for setting up a coach factory in Kerala. It is indeed a very heartening step. I hope that the Government will take an expeditious decision on the report of this team. In this context I may mention that Palghat is the most suitable place for setting up this factory. All the required facilities are available there. Therefore, I earnestly request the Government to take speedy steps to set up this coach factory at Palghat itself.

(iv) Need to take steps to increase the rice production in the country

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak): In spite of the commendable achievements made in our agriculture, especially on the rice front, breaking the stagnation level of 53 to 54 million tonnes and reporting a score of 57 million tonnes in the year 1983-84, India's achievement in per hectare yield in rice is actually poorer than many countries, including some developing ones.

The experience with high-yielding varieties has shown that when the ecology of the rice

*Original speech was delivered in Malayalam.